

प्रेषक,

उदयवीर सिंह यादव,
अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2018

विषय-राज्य की कारागारों में ई-प्रिजन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-991/XX-4/2018-1(43)/2018, दिनांक 11.06.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य की कारागारों में ई-प्रिजन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्षक 2056-जेलें-101-जेलें-01-केन्द्र सहायित योजनों-0101-ई प्रिजन योजना के मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 53.00 लाख (रू0 तरेपन लाख मात्र) की स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आपके पत्रांक-मेमो/ई0प्रिजन/2018-19, दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्रकरण में रू0 131.17 लाख की डी0पी0आर0 उपलब्ध कराते हुये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की कारागारों में ई-प्रिजन के क्रियान्वयन हेतु कुल रू0 131.17 लाख की स्वीकृति वर्णित शासनादेश दिनांक 11.06.2018 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. ई-प्रिजन योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित तकनीकी स्पेशीफिकेशन के सम्बन्ध में तकनीकी समिति की संरुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. ई-प्रिजन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि रू0 21.17 लाख की प्राप्ति भारत सरकार से सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग सहमति एवं उनके आ0शा0 संख्या-119 मतदेय / XXVII(5)/2018, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
अपर सचिव

संख्या-1171/XX-4/2018-1(43)/2018, तददिनांक
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-5
6. माई फाइल।

आज्ञा से,
Ashish
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव

संख्या- /XX-4/2018-1(43)/2018